



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 27 दिसम्बर, 2000/6 पौष, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 27 दिसम्बर, 2000

संख्या 1-78/2000-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 140 के अन्तर्गत “हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का

3119-राजपत्र/2000-27-12-2000—1,399.

(4781)

मूल्य : 1 रुपय।

विधेयक संख्यांक 21)'' जो मात्र दिनांक 27 दिसम्बर, 2000 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2000 का विधेयक संख्यांक 21

हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (1968 का 24) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर संक्षिप्त नाम (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2000 है ।

2. हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 की धारा 22 की धारा 22 का उप-धारा (4) में, “ले जाए जा रहे” शब्दों के पश्चात् और “माल की ऐसी” शब्दों संशोधन । से पूर्व शब्द “कराधेय” का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 की धारा 22 के अधीन माल गाड़ी इत्यादि में ले जाए गए, गैर-कराधेय माल के बारे में घोषणा देने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। इस कमी का, अनैतिक व्यक्तियों द्वारा कर अपवंचन करने के औजार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए, उपर्युक्त अधिनियम का संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है ताकि गैर-कराधेय माल के बारे में घोषणा देना अनिवार्य बनाया जाए।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रवीण शर्मा,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख 2000.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 कर उद्गृहीत करने, बढ़ाने या कम करने का कोई उपबन्ध नहीं करता है। विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान प्रशासनिक तन्त्र द्वारा प्रशासित किए जाएंगे और इससे राज कोष पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 21 of 2000.

THE HIMACHAL PRADESH GENERAL SALES TAX (THIRD
AMENDMENT) BILL, 2000

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A
BILL

*further to amend the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968
(Act No. 24 of 1968).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the
Fifty-first Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh General Sales Tax
(Third Amendment) Act, 2000.

Short title.

2. In section 22 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968,
in sub-section (4), after the words “prescribed of the” and before the
words “goods carried”, the word “taxable” shall be omitted.

Amendment
of section
22.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 22 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968, there is no provision for furnishing of declaration in respect of non-taxable goods carried in goods vehicles etc. This deficiency is being exploited by unscrupulous persons as a tool of evasion of tax. As such, it has been considered necessary to amend the Act *ibid*, so as to make it essential to furnish declaration in respect of non-taxable goods also.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

PRAVEEN SHARMA,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
Dated the.....2000.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill does not seek to levy, enhance or reduce any taxes. The provisions of the Bill when enacted will be administered by the existing administrative machinery and will not result in additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-